[2008] 16 एस. सी. आर 750

A भुवनेश्वर यादव

बनाम

राज्य सरकार बिहार एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं० 1893 ऑफ 2008)

नवम्बर 28, 2008

B **[डॉ० अरिजीत पसायत एवं डॉ० मुकंदकम शर्मा, जेजे.]**

C दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 - जमानत – प्रदत्त करना - कारणों को इन्द्राज करना - आवश्यकता - अभियुक्त को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया - उच्च न्यायालय ने अपील के लंबित रहने के दौरान दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया - हालांकि, छह महीने के बाद जमानत के लिए प्रार्थना को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी गई - इसके बाद, जमानत दी गई - की गई
D प्रार्थना - की शुद्धता - माना गया: जमानत के लिए प्रार्थना को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश, हालांकि यह देखा गया कि जमानत पहले खारिज कर दी गई थी, यह नहीं दर्शाता है कि जमानत के लिए अधिकार था – यह दिमाग के पूर्ण गैर-प्रयोग को दर्शाता है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

E इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा गैर-तर्कसंगत आदेश द्वारा उत्तरदायी संख्या 2 और 3 को जमानत देना उचित था, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया था।

F न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

G अवधारित किया: 1.1 जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है , न कि किसी सामान्य मामले के रूप में। आदेश में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है , खासकर जहां एक आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। जमानत के आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर विचार करना आवश्यक है:

(i) दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति; (ii) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका; (iii) आरोप के समर्थन में न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है। ऐसे कारणों का कोई भी आदेश मस्तिष्क के गैर -प्रयोग से पीड़ित होता है। जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन और प्रकरण की विशेषताओं के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए। [पैरा 8, 9 और 10] [754-एच; 755-ए-डी]

1.2 वर्तमान मामले में, दोषसिद्धि दर्ज करते समय अभियुक्तों के अपराध के बाबत संतुष्टि प्राप्त की जा चुकी है। जब दोषसिद्धि दर्ज होने के बाद अपील के लंबित रहने के दौरान आवेदन किया जाता है तो स्थिति अलग नहीं थी। उच्च न्यायालय ने देखा कि पहले जमानत खारिज कर दी गई थी , लेकिन छह महीने बाद दोबारा प्रार्थना करने की छूट दी गई थी। यह किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि जमानत पाने का अधिकार था। उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से दिमाग के गैर-अनुप्रयोग करने को दर्शाता है और इसलिए, उक्त को ख़ारिज कर दिया गया है। जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार कर तर्कसंगत आदेश के द्वारा निस्तारित किया जाएगा। [पैरा 11 और 14] [755-ई; 756-सी-डी]

उमर उस्मान चमड़िया बनाम अब्दुल और अन्य जेटी 2004 (2) एससी 176; वी.डी. चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2005 (7) स्केल 68; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह एवं अन्य 2002 (3) एससीसी 598; पूरन आदि बनाम रामबिलास एवं अन्य आदि 2001 (6) एससीसी 338; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अन्य जेटी 2004 (3) एससी 442; चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य जेटी 2004 (6) एससी 540 और अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद 2005 (7) एससीसी 326, संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ:

जेटी 2004 (2) एससी 176	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 6**
2005 (7) स्केल 68	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 7**
2002 (3) एससीसी 598	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 10**
2001 (6) एससीसी 338	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 10**
जेटी 2004 (3) एससी 442	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 10**
जेटी 2004 (6) एससी 540	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 12**
2005 (7) एससीसी 326	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 12**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1893/2008

आपराधिक अपील संख्या 90/2004 (डी.बी.) में पटना उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय दिनांक 14.3.2007 से

अपीलकर्ता की ओर से अखिलेश कुमार पांडे।

प्रतिवादी की ओर से मनीष कुमार एवं गोपाल सिंह।

न्यायालय का निर्णय उद्घोषित किया गया

डॉ० अरिजीत पसायत, जे. 1. अनुमति स्वीकृत।

यह अपील पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आलोच्य आदेश के विरुद्ध योजित की गई है, जिसमें प्रतिवादीगण 2 और 3 को जमानत दी गई थी, जिन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया था। आयुध अधिनियम, 1959 (संक्षेप में 'शस्त्र अधिनियम') की धारा 27 के तहत दो अन्य व्यक्तियों, निर्मल सिंह और शिव जनम सिंह को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। चार अन्य आरोपियों को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। प्रतिवादी 2 और 3 ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 90/2004 योजित की जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता, सूचक भी उपस्थित हुआ है।

हालाँकि जमानत के लिए प्रार्थना पहले अपील के लंबित रहने के दौरान की A
गई थी, लेकिन उन्हें 23.3.2004 और 24.8.2006 को खारिज कर दिया गया
था। हालाँकि, बाद के मामले में छह महीने के बाद जमानत के लिए प्रार्थना
को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसे पुनः दिनांक 14.3.2007 B
को बनाया गया जिसकी अनुमति आक्षेपित आदेश द्वारा दी गयी है।

3. अपीलकर्ता के अनुसार , उच्च न्यायालय का आक्षेपित/आलोच्य
आदेश पूरी तरह से दिमाग के गैर-अनुप्रयोग करने को प्रदर्शित करता है। इस
बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि जमानत आवदेन की प्रार्थना को
पहले दो मौकों पर खारिज कर दिए जाने के बाद आखिरकर क्यों स्वीकार C
किया गया, जबकि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील- **राज्य ने अपीलकर्ता के रुख का समर्थन
किया।**

5. नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी 2 और 3 की ओर से कोई D
उपस्थित नहीं हुआ।

6. इस समय, उमर उस्मान चमड़िया बनाम अब्दुल और अन्य मामले
में इस न्यायालय के एक फैसले पर ध्यान देना उचित होगा कि (जेटी 2004
(2) एससी 176)। पैरा 10 में, इसे इस प्रकार देखा गया: E

"हालांकि, निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें इस मामले के दूसरे पहलू पर ध्यान
देना चाहिए, जिसने हमारे लिए कुछ चिंता पैदा की है। हाल के दिनों में, हमारे F
पास कई बार यह देखने का अवसर था कि उच्च न्यायालयों ने आपराधिक
कार्यवाही में अधिवक्ता द्वारा दिखाई गई रियायतों को दर्ज किया है। उन आदेशों
में भी कोई कारण बताने से बचें, जिनके द्वारा निचली अदालतों के आदेशों को
उलट दिया जाता है। हमारी राय में, यह उचित नहीं है यदि ऐसे आदेश अपील G
योग्य हैं, चाहे वह पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिखाई
गई रियायत के आधार पर हो या आधार यह है कि विस्तृत कारण बताए जाने
से निचली अदालतों के समक्ष भविष्य में होने वाले मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ सकता है। उच्च न्यायालय को, जब तक कि बहुत अच्छे कारण न हों, उन H
आधारों को इंगित करने से बचना नहीं चाहिए जिन पर उनके आदेश
व्यावधारित हैं।

क्योंकि जब प्रकरणों को अपील में लाया जाता है , तो अपीलीय न्यायालय के पास यह जानने का हर कारण होता है कि विवादित आदेश किस आधार पर दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि निचली अदालत के आदेश से सहमत होते समय , उक्त अपीलीय न्यायालय के लिए कारण बताना आवश्यक न हो, लेकिन निचली अदालतों के ऐसे आदेशों को उलटते समय ऐसा नहीं है। उक्त अदालत के लिए आधार या आधार बताए बिना आदेश पारित करना सुविधाजनक हो सकता है , लेकिन ऐसे विवादित आदेशों की शुद्धता पर विचार करते समय अपील अदालत के लिए यह निश्चित रूप से सुविधाजनक नहीं है। कारणों को बहुत विस्तृत या विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा न हो कि इससे पक्षकारों के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन विवादित आदेश को पारित करने के लिए तर्क की प्रक्रिया का पर्याप्त संकेत अवश्य होना चाहिए। तर्कसंगत आदेश देने की आवश्यकता विधि की एक मूलभूत आवश्यकता है जिसका अनुपालन सभी अपीलीय आदेशों में किया जाना चाहिए। कुछ इसी तरह की स्थिति में इस न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी (एआईआर 1984 एससी 444) के मामले में गैर-भाषी आदेशों के प्रथा की निंदा की है।

7. इन पहलुओं को हाल ही में वी. डी. चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2005 (7) स्केल 68) में उजागर किया गया था।

8. सरसरी तौर पर देखने पर भी, उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से मस्तिष्क के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है। यद्यपि जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए, फिर भी जमानत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण है , लेकिन प्रकरण की खूबियों का विस्तृत अन्वेषण आवश्यक नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है, न कि किसी सामान्य प्रकरण के रूप में।

9. आदेश में यह बताने की आवश्यकता है कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत विशेषतः क्यों दी जा रही है,

खासकर जहां किसी आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। जमानत के आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालयों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है, वे हैं:

1. दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता एवं समर्थन की प्रकृति में प्रस्तुत साक्ष्य;
2. साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका;
3. आरोप के समर्थन में न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है।

10. ऐसे कारणों का कोई भी आदेश विवेक के गैर -प्रयोग से ग्रस्त है जैसा कि इस न्यायालय ने राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य [(2002) 3 एससीसी 598], पूरन आदि बनाम रामबिलास व अन्य आदि [(2001) 6 एससीसी 338)], और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अन्य में [जेटी 2004 (3) एससी 442] के मामले में नोट किया था

11. जब दोषसिद्धि दर्ज होने के बाद अपील के लंबित रहने के दौरान आवेदन किया जाता है तो स्थिति अलग नहीं होती है। दोषसिद्धि दर्ज करते समय अभियुक्तों के अपराध के बारे में संतुष्टि प्राप्त कर ली गई है।

12. उपरोक्त पारिस्थितिकी को इस न्यायालय द्वारा चमन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (जेटी 2004 (6) एससी 540) और अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद (2005 (7) एससीसी 326) के प्रकाश में डाला गया।

13. **वर्तमान अपील में लागू आदेश इस प्रकार है:**

"अपीलकर्ताओं, राज्य और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 24.8.2006 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं की जमानत की प्रार्थना को छह महीने के बाद नवीनीकृत करने की छूट के साथ खारिज कर दिया गया था।

B उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं, लल्लू सिंह और धनु सिंह को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रत्येक को 10,000/- रुपये के निजी बंधपत्र व समतुल्य धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अपील की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सम्बन्धित सत्र विचारण संख्या 32/2001 सम्बन्धित न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, आरा, भोजपुर।"

C 14. उच्च न्यायालय ने देखा कि पहले जमानत खारिज कर दी गई थी , लेकिन छह महीने के बाद प्रार्थना को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि जमानत पाने का अधिकार था। उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश पूरी तरह से मस्तिष्क के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है
D और इसलिए इसे ख़ारिज कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है। जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार किया जाएगा और तर्कसंगत आदेश द्वारा निस्तारित किया जाएगा। यदि प्रतिवादीगण को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो उन्हें तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

एन.जे. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद नवनीत कुमार, अपर सिविल जज(जू०डि०) न्यायालय कक्ष सं० 05, मथुरा द्वारा किया गया है।